

पेटेंट नीति पर अमेरिकी विरोध को चुनौती

वाशिंगटन, प्रेड : भारत की पेटेंट नीति पर आंखें तरेने वाले अमेरिका को अब वैश्विक संगठनों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। जेनेवा स्थित एसोसिएशन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत पर दबाव बनाए जाने को लेकर अमेरिका और इसकी फार्मा लॉबी की आलोचना की है।

इस एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई ग्लोबल व्यापार तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस गैर सरकारी संगठन ने कहा, 'हर देश को दवाओं की पहुंच बढ़ाने और अपनी जनस्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप पेटेंट प्रणाली लागू करने का अधिकार है। हम भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों पर अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव का कड़ा विरोध करते हैं।'

भारत अपने जन स्वास्थ्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र में लचीलेपन का रास्ता अपना रहा है। संगठन के प्रतिनिधि रोहित मालपानी ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कमिशन (यूएसआईटीसी) को अपने इस रुख से अवगत कराया है। यूएसआईटीसी ने भारत की व्यापार, निवेश व औद्योगिकी नीतियों के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर के मसले पर जांच के तहत इसी हफ्ते



दिखाया आईना

♦ जेनेवा स्थित संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जताया एतराज

♦ कहा, भारत को अपने स्वास्थ्य तंत्र की सुरक्षा का पूरा हक

सुनवाई की है। मालपानी ने कहा कि भारत की ओर से उठाए गए कदम पूरी तरह से ग्लोबल व्यापार नियमों और भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं।

इस तरह के हमले वैश्विक व्यापार तंत्र और भारतीय न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हैं। भारतीय न्यायपालिका मौजूदा विचार-विमर्श के बीच निर्णय लेने की जिम्मेदारी उठा रही है। जन स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

दुनियाभर के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद अहम हैं। भारत को विकासशील देशों की फार्मसी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में इस फार्मसी को खोना मरीजों और चिकित्सा सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। एसोसिएशन ने पिछले एक साल से भारत के खिलाफ अभियान चला रही अमेरिकी फार्मा लॉबी को आड़े हाथ लिया है।

उसने कहा है कि चिकित्सा संबंधी नवाचारों के लिए धन जुटाने को दवाओं की मनमाना ऊंची कीमतें तय करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों के एकाधिकार का रास्ता अपनाना गलत तरीका है। दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण इनकी पहुंच नहीं बढ़ पाती। साथ ही विकासशील देशों में लोग जिन बीमारियों से पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए नवाचारों को बढ़ावा नहीं मिलता।

इन देशों में मरीजों की खरीद क्षमता कम है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं मिलता। संपत्ति अधिकारों का प्रभुत्व ऐसे देशों में केवल नवाचारों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह एक असफल कारोबारी मॉडल भी है।